

Q- भारत के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के वर्तमान एवं भविष्य में अपेक्षित प्रभावों की चर्चा करते हुए वांछित वर्गों, मीडियाओं और वृद्धों पर इन प्रभावों के परिणामों का विश्लेषण करें। (250 शब्द)

भारत में पर्यावरण संरक्षण

Environmental Protection in India

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (EPA)

प्रष्ठभूमि -

- ① 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण को लेकर व्यापक उपायों के अपनाने पर आम सहमति बनी थी।
- ② देशों से यह अपेक्षित था कि उनके द्वारा व्यापक प्रावधानों के साथ पर्यावरण

संरक्षण के लिए) अधिनियम लागू जाएंगे।

③ Polluter pays सिद्धांत पर भी आम सहमति थी जिसका आशय ऐसे प्रावधान से था जहाँ किसी भी पर्यावरणीय क्षति के लिए जिम्मेदार व्यक्ति या एजेंसी के द्वारा ही पुनर्स्थापना या क्षतिपूर्ति का काम किया जाएगा।

④ भारत के द्वारा इस प्रकार के एक व्यापक अधिनियम को लागू करने में काफी विलम्ब रहा पर नेपाल जैसे नजदीकी 1984 के बाद इस दिशा में प्रयास तेज हो गए।

⑤ अंततः यह अधिनियम 1986 में पारित हुआ और इसके तहत कई प्रकार की नियमावलियाँ समय-समय पर लागू की गयीं।

प्रावधान →

1. पर्यावरण की व्यापक परिभाषा, जिसे मनुष्यों के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक वातावरण तथा इसके विभिन्न घटकों के अंतर्संबंधों के रूप में देखा गया है।
2. प्रदूषण की व्यापक परिभाषा - मनुष्यों के भौतिक, रासायनिक व जैविक वातावरण में कोई भी ऐसा परिवर्तन जिससे वातावरण के घटक की उपयोगिता कम हो जाए या कोई घटक मनुष्यों के लिए हानिकारक हो जाए।
3. प्रदूषक कोई ऐसा पदार्थ है जिसकी एक विशेष मात्रा में होने से प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती है।
4. इस अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार और उसकी एजेंसियों को व्यापक

अधिकार दिए गए हैं -

(a) पर्यावरण संरक्षण के अलग उद्देश्यों के लिए आवश्यकतानुसार नियम जारी करना।

(b) जल, वायु एवं पर्यावरण के अन्य घटकों की गुणवत्ता के मानक तय करना तथा उन मानकों को एजेंसियों के द्वारा लागू करना।

इस संदर्भ में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मानक तय करती है और राज्य स्तरीय बोर्ड इन मानकों को लागू करते हैं। राज्य बोर्ड के अधिकारियों द्वारा संभावित रूप से प्रदूषण करने वाली फैक्ट्रियों की समय - समय पर निगरानी की जाती है।

(c) ऐसे उद्योग या एजेंसी जिनके द्वारा तय मानकों का अनुपालन नहीं किया

जाता उन पर दण्ड का भी प्रबधान है।

- ① विशेष क्षेत्रों में कुछ उद्योगों या मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाना।
- ② कुछ क्षेत्रों को आवश्यकतानुसार पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील घोषित करना।

EPA, 1986 के अंतर्गत उठाए गये महत्वपूर्ण कदम →

- ① कई प्रकार की नियमावली -
 - जैव - प्रौद्योगिकी के उत्पादों से सुरक्षा के नियम
 - खतरनाक / जोखिम भरे अपशिष्टों के लिए नियम
 - e-waste के नियम
 - Medical waste के नियम
 - ठोस अपशिष्टों को लेकर दिशा - निर्देश

• Single use plastic को लेकर नियम।

② पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की व्यवस्था लागू हुई।

③ • तटीय विनियमन क्षेत्र

• Ecological Sensitive Area

• Marine Protected Area की व्यवस्था।

कुछ अन्य अधिनियम →

जल प्रदूषण बचाव एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974



① भारत में जल प्रदूषण के बचाव एवं नियंत्रण के लिए।

② जल संसाधनों के गुणवत्ता के मानक

जल प्रदूषण- बचाव एवं नियंत्रण उप-कर अधिनियम, 1977

वायु प्रदूषण बचाव एवं नियंत्रण अधिनियम, 1981

स्थापित किए गए।

- ③ केन्द्र एवं राज्य स्तरों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए गए।
- ④ मानकों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में दण्ड का प्रावधान, जिसमें प्रदूषक उद्योगों को बन्द कराने तक का प्रावधान है।

जल प्रदूषण - बचाव एवं नियंत्रण उपकरण अधिनियम, 1977 →

1. प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के वित्तीय सहायता के लिए लाया गया अधिनियम।
2. इसके अंतर्गत स्थानीय निकायों और उद्योगों को अपने जल की खपत की बिल के अतिरिक्त उपकरण भी देने की आवश्यकता स्थापित की गयी।
3. उपकरण से प्राप्त धनराशि का उपयोग

प्रदूषण के स्तरों की निगरानी और नियंत्रण के उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

4. उपकरण की दर जल के उपयोग, उद्देश्य और उपयोग की मात्रा के आधार पर तय किया जाता है।

वायु प्रदूषण बचाव एवं नियंत्रण अधिनियम - 1986

① भारत में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं वायु की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एक अधिनियम।

② केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा वायु गुणवत्ता के मानक तय किए जाते हैं।

③ इन मानकों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य बोर्डों की होती है।

④ कुछ विशेष क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के कठोर मानक लागू किए जा सकते हैं जो किसी समय विशेष के लिए भी हो सकता है।

⑤ इस अधिनियम के अंतर्गत कारखाने और वाहन मुख्यतः नियंत्रित किए जाते हैं।

